(मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण (Oath of Ministers) –

प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची तीन में दिये गये प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है।

Every Minister, including the Prime Minister, has to make and take the oath of office and secrecy before the President in the format given in Schedule Three.

शपथ (oath) → PM + Minister

↳ अनुसूची (Schedule-3)

↳ 2 प्रकार (types)
- पद (Post)
- गोपनीय (secrecy)

↳ शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलायी जाती है।

PM + COM

⇓

सरकार

मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल tenure of council of ministers

मंत्रिपरिषद् तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तब कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।

The Council of Ministers remains in existence only as long as it enjoys the confidence of the Lok Sabha.

PM + CoM => कार्यकाल => 5 वर्ष

Minister (मंत्री) => PM के विश्वास पर

प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति से किसी मंत्री को उसके पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है।

The Prime Minister can recommend to the President to remove any minister from his post at any time.

PM Minister ⇒ न्यूनतम आयु Minimum Age ⇒ 25 वर्ष

मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या

Number of members of council of ministers

किन्तु 91 वें संविधान संशोधन-2003 द्वारा मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोक सभा के कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

But by the 91st Constitutional Amendment-2003, the total number of members in the Council of Ministers including the Prime Minister shall not exceed 15 percent of the total number of members of the Lok Sabha.

सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)

(अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि, 'मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(Article 75(3) states that, 'The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.

Q: ⇒ केंद्रीय मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?

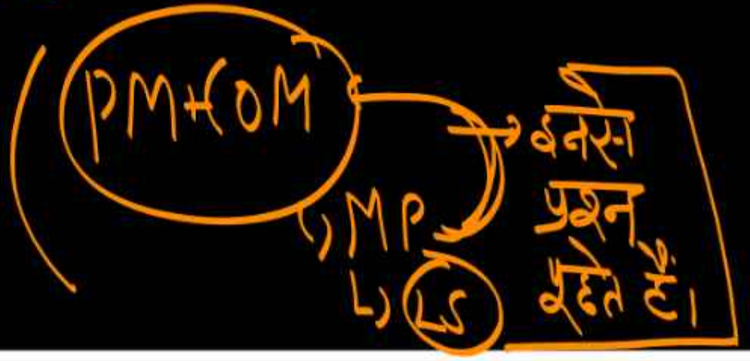

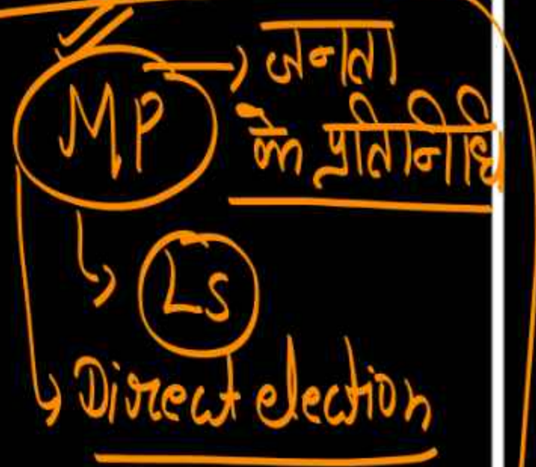

अनुच्छेद-78 के तहत प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य संवाद की एक कड़ी बनाया गया है

Under Article 78, the Prime Minister has been made a link of communication between the Council of Ministers and the President.

प्रशासन या विधान सम्बन्धी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे।

Inform the President about all decisions of the Council of Ministers related to administration or legislation.

Art: 78 ⇒ PM का कर्तव्य (Duty of PM)

⇓ राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के मध्य मध्यस्थ की भूमिका

Play the role of Mediator between President and CoM.

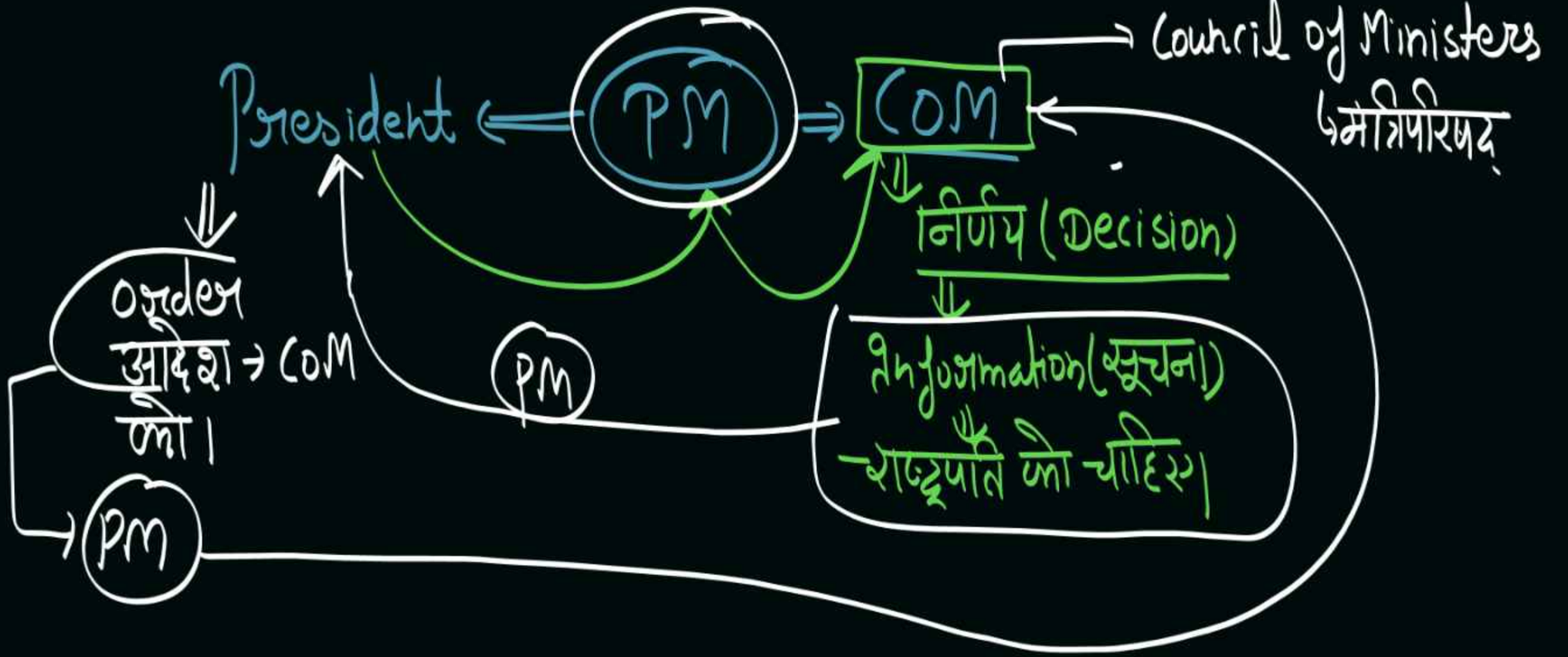

केंद्र — राज्य

PM ⇒ CM

मंत्रिपरिषद् ⇒ मंत्रिपरिषद्

राष्ट्रपति → राज्यपाल (Governor)

लोकसभा → विधानसभा (Legislative Assembly)

राज्यसभा → विधानपरिषद्

राज्य मंत्रिपरिषद (The State Council of Ministers)

अनु. 163 के अनुसार कार्यों के निर्वाह में उसे (राज्यपाल को) सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।

According to Article 163, there will be a Council of Ministers to assist him in discharging his functions, headed by the Chief Minister.

मुख्यमंत्री की नियुक्ति Appointment of the chief Minister

अनु. 164 (1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा।

CM + COM ⇒ नियुक्ति

Article 164(1) states that the Chief Minister shall be appointed by the Governor and other Ministers shall be appointed by the Governor in consultation with the Chief Minister.

⇒ विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल (Party)
के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं।

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति Appointment of the Other Minister

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। 91 वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधान सभा की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत नियत किया गया है

The Governor appoints other ministers on the advice of the Chief Minister. By the 91st Constitutional Amendment (2003), the maximum number of ministers in the State Council of Ministers has been fixed at 15 percent of the total number of members of the Legislative Assembly including the Chief Minister.

मंत्रियों की योग्यताएं Qualifications of the Minister + CM

विधानमण्डल के किसी सदन के सदस्य हों। परन्तु मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्रि परिषद में शामिल कर सकता है जो विधानमण्डल का सदस्य नहीं है किन्तु शर्त यह है कि उसे 6 माह के भीतर विधानमण्डल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है।

Must be a member of any House of the Legislature. But the Chief Minister can include a person in the Council of Ministers who is not a member of the Legislature but the condition is that he must become a member of the Legislature within 6 months.

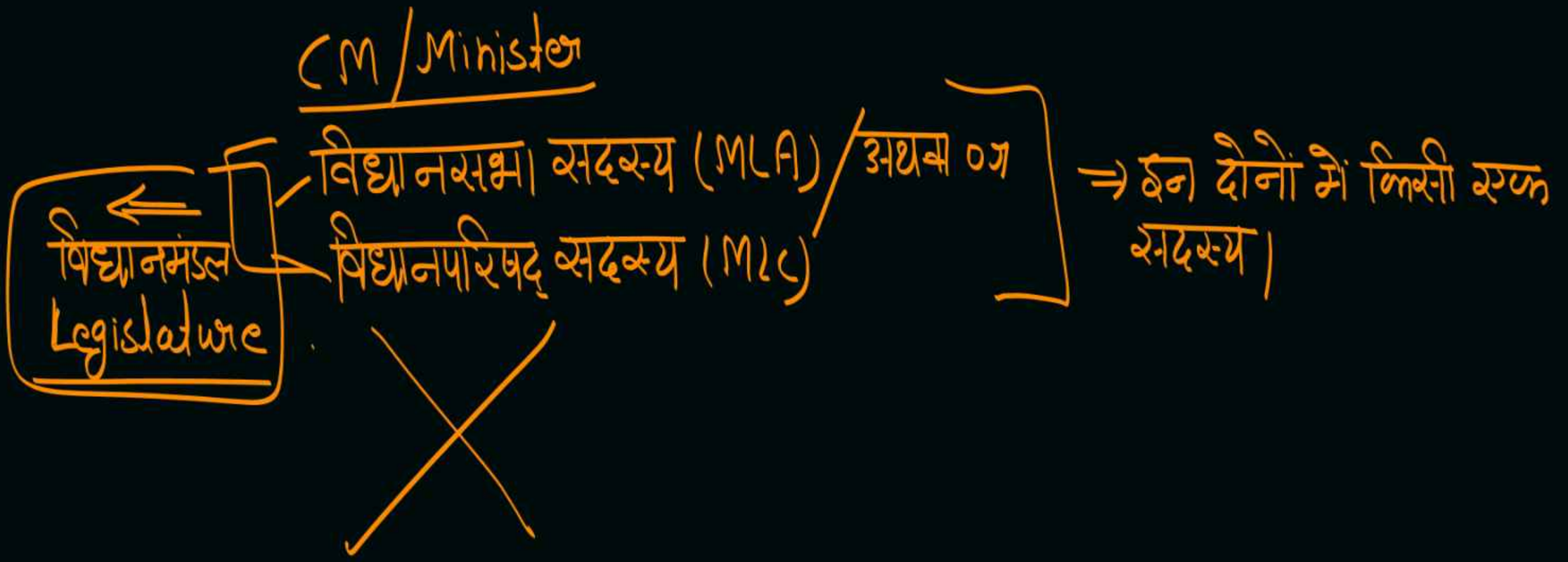

CM / Minister

विधानसभा सदस्य (MLA) / अथवा or

विधानपरिषद् सदस्य (MLC)

⇒ इन दोनों में किसी एक सदस्य।

← विधानमंडल

Legislature

मंत्रियों द्वारा शपथ-ग्रहण Oath by the Minister

राज्यपाल द्वारा शपथ दिलायी जाती है। प्रथम पद की शपथ तथा दूसरी गोपनीयता की शपथ। शपथ का प्रारुप अनुसूची तीन में दिया गया है।*

The oath is administered by the Governor. First is the oath of office and second is the oath of secrecy. The format of the oath is given in Schedule 3.*

मंत्रियों की श्रेणियाँ Cotegory of Ministers

मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती हैं-

There are three categories of ministers-

(i) कैबिनेट मंत्री या मत्रिमण्डल के सदस्य,

Cabinet Ministers or Members of the Cabinet,

(ii) राज्यमंत्री और Ministers of State and

(iii) उपमंत्री Deputy Ministers

+PM

=> COM

मंत्रिपरिषद का कार्यकाल Term of office of the C.O.M.

सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल जितना, अर्थात् 5 वर्ष तक हो सकता है।

Generally, the maximum tenure of the Council of Ministers can be equal to the tenure of the Legislative Assembly, i.e. 5 years.

Minister का कार्यकाल
Tenure of Minister

मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर, विश्वास समाप्त होने पर मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहकर हटवा सकते हैं।

Q. CM + Minister कौन हटायेगा? ⇒ राज्यपाल (Governor)

Q. ⇒ CM + Minister किसके प्रसाद पर्यंत (Pleasure of office) पद धारण करेंगे?

↳ Governor

सामूहिक उत्तरदायित्व Collective Responsibility

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है*

↳ House of People (जनता का सदन)
↳ MLA

The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly*

(CM + Ministers) → प्रश्न पूछेगा MLA's

अनुच्छेद 167 के तहत, मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णय राज्यपाल को संसूचित करे,

Under Article 167, it is the duty of the Chief Minister to communicate to the Governor all decisions of the Council of Ministers relating to the administration and legislation of the state.

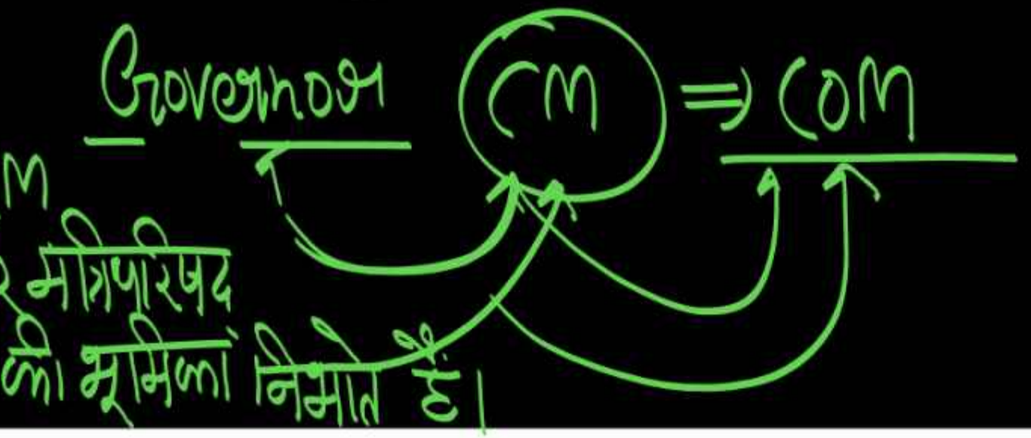

Art. 167 ⇒ CM राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं।

Art 167 ⇒ Duty of CM (CM के कर्तव्य)।
⇒ Play the role of Mediator between Governor & CoM.

भारत का महान्यायवादी The Attorney General of India

भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है तथा भारत क सरकार को विधिक मामलें पर सलाह (Advice) देता है। वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है।

He is the highest legal officer of the Government of India and advises the Government of India on legal matters. He also represents the Government of India in the Supreme Court and High Courts.

अनुच्छेद 76 (1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है* तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त (During the Pleasure of the President) अपना पद धारण करता है।* अतः राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है।

According to Article 76 (1) the Attorney General is appointed by the President on the advice of the Union Council of Ministers* and holds office during the pleasure of the President.* Hence, the President can remove him at any time.

वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त भी हो सकता है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है ।

He can also resign by submitting his resignation to the President. The Attorney General is paid remuneration determined by the President. The President appoints a person as the Attorney General who is qualified to become a judge of the Supreme Court.

अनु. 124 (3) (i) एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या (ii) एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो अथवा (iii) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता (Jurist) हो ।

Article 124 (3) (i) has been a Judge of one or more High Courts for five years, or (ii) has been an advocate of one or more High Courts for ten years, or (iii) is a distinguished jurist in the opinion of the President.

महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई (Audience) का अधिकार होता है अनु. 88 के तहत् महान्यायवादी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा विचार व्यक्त कर सकता है; किन्तु मतदान नहीं कर सकता है;

The Attorney General has the right of audience in all the courts of India. Under Article 88, the Attorney General has been given the right to participate in the proceedings of both the houses of the Parliament and express his opinion; but cannot vote;

राज्य का महाधिवक्ता The Advocate General of State

राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए, अनु. 165 के तहत महाधिवक्ता (The Advocate General) नामक प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। *

To give legal advice to the states, Article 165 provides for an authority called The Advocate General. The Advocate General is the highest legal officer of the state. *

राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, संबन्धित राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। (अनु. 217 (3) वह भारत का नागरिक हो तथा कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो

The Governor can appoint any person who is qualified to be appointed as a Judge of the High Court as the Advocate General of the concerned state. (Article 217 (3) He should be a citizen of India and should have held a judicial office for at least 10 years or should have practised as an advocate in a High Court for at least 10 years

महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त (During the Pleasure) अपना पद धारण करता है अर्थात् उसकी पदावधि नियत नहीं है तथा ऐसा पारिश्रमिक (Remuneration) प्राप्त करता है जो राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाय।

The Advocate General holds office during the pleasure of the Governor, i.e., his tenure is not fixed and he receives such remuneration as may be determined by the Governor.

महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य विधि सम्बन्धी ऐसे सब विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देना है जिन पर राज्यपाल उससे परामर्श माँगे महाधिवक्ता को राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलेने का अधिकार है किन्तु मतदान का अधिकार नहीं है* (अनु. 177)। उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। *

The main work of the Advocate General is to advise the State Government on all such law related matters on which the Governor seeks his advice. The Advocate General has the right to participate and speak in the proceedings of the State Legislature but does not have the right to vote* (Article 177). He has the right to be heard in any court of the State.